प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 07 – 14 नवम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

सीबीआई प्रकरण में फैसले के कगार पर पहुंचा वीरभद्र मामला

शिमला/शैल। वीरभद्र के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में अब फैसले के दौर में पहुंच गया है। पिछली पेशी में हिमाचल सरकार का

पक्ष रख रहे प्रदेश के महाधिवक्ता को अपना पक्ष संक्षेप में लिखित में 2 दिसम्बर को अदालत के सामने रखने को कहा है। उसी दिन सीबीआई इस याचिका से जुड़े सारे वादीयों के दावों का जबाव देगी। इस जबाव में सीबीआई को जितना भी समय लगेगा उसके बाद इस मामले का फैसला आना है। यदि वीरभद्र सिंह की याचिका स्वीकार हो जाती है तो पूरा प्रकरण वहीं समाप्त हो जायेगा और यदि यह याचिका अस्वीकार हो जाती है तो फिर इसमें चालान ट्रायल कोर्ट में दायर हो जायेगा। हिमाचल सरकार, वीरभद्र और अन्य याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस मामले में सीबीआई का प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना या किसी अदालत के निर्देशों के बिना जांच का क्षेत्राधिकार ही नही बनता है और ऐसे में सीबीआई की सारी कारवाई गैर कानूनी हो जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रदेश के महाधिवक्ता को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जांच अवधि के काल में वीरभद्र केन्द्र में मन्त्री थे और इस कारण दिल्ली क्षेत्राधिकार बन जाता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस मामले में चालान दायर होना तय है।

जैसे जैसे यह मामला फैसले की ओर बढ़ रहा है उसी अनुपात में ईडी ने भी इस प्रकरण में अपनी शेष बची जांच तेज कर दी है। पिछले एक परववाड़े में ईडी की टीम दो बार रामपुर और शिमला का दौरा कर चुकी है। ईडी ने रामपुर के एक ऐडवोकेट राम आसरा से भी कुछ जानकारी हासिल की है। राम आसरा भी वीरभद्र के सेब बागीचे के प्रबन्धन से [illegible] जुड़े रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि वीरभद्र ने जो पुश्तैनी संपति विक्रमादित्य और अन्य के नाम ट्रांसफर की है उसका रिकार्ड भी ऐजैन्सी ने हासिल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी टीम का दूसरा दौरा सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद हुआ है और इसमें आयकर विभाग के लोग भी शामिल थे। चर्चा के मुताबिक कालाधन और बेनामी संपति की घोषणा योजना की 30 सितम्बर को अवधि समाप्त होने के बाद अचानक कई बैंक खाते खुलने की सूचना ईडी और आयकर विभाग को मिली थी। उसी की प्रमाणिकता जांचने के लिये ईडी टीम ने दस्तक दी थी। माना जा रहा है कि इन खातों की जानकारी के लिये आरटीआई का भी सहारा लिया गया है। क्योंकि आरटीआई के

- एक पखवाडे में ईडी की दो बार दस्तक
- 30 सितम्बर के बाद खुले बैंक खातों की जानकारी में जुटा आयकर और ईडी
- वीरभद्र के विरोधी फिर हुए सक्रिय चण्डीगढ में की बैठक

तहत खाता धारक की जानकारी तो नही मिल सकती है। लेकिन बैंक के पास अमुक अवधि में खुली खातों की संख्या की जानकारी को नहीं रोका जा सकता है । आयकर और ईडी सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी फैसले के बाद तीन बड़े बैंको के बड़े अधिकारियों की सरकार के एक बड़े अधिकारी और एक राजनेता के साथ हुई बैठक की जानकारी मिलने के बाद यह ऐजैन्सीयां हरकत में आयी है और अब बराबर निगरानी बनाये हुए हैं। इस सद्धर्भ में ईडी ने राज्य सहकारी बैंक को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है।

दूसरी ओर अदालत में मामला फैसले के कगार पर पहुंचने और ईडी द्वारा अपनी जांच तेज कर दिये जाने के साथ ही वीरभद्र विरोधीयों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है यदि वीरभद्र सिंह के खिलाफ चालान अदालत में दायर हो जाता है तो उन पर पार्टी के भीतर भी त्याग पत्र देने का दबाव आ सकता है। ऐसे में एक वर्ग का मानना है कि वीरभद्र पद त्यागने की बजाये विधानसभा भंग करवाकर चुनाव में जाने की रणनीति पर चलेंगे। लेकिन दूसरा वर्ग चुनाव की बजाये नया नेता लाने की वकालत कर रहा है। इस संद्धर्भ में पार्टी के कुछ विधायकों की चण्डीगढ में बैठक हुई है। इस बैठक की जानकारी प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी को भी रही है। बल्कि सूत्रों का दावा तो यहां तक है कि इस बैठक में सोनी का एक विश्वस्त भी शामिल रहा है। इस बैठक की जानकारी पंजाब की प्रभारी आशा कुमारी को भी रही है। बैठक में शामिल रहे एक विधायक ने दावा किया है कि पार्टी हाईकमान को विधायकों की चिन्ता और उनके फैसले से सूचित करवा दिया गया है। बैठक में पार्टी की एक जुटता बनाये रखने के लिये कौल सिंह को मुख्यमंत्री और जी एस बाली को उपमुख्यमन्त्री बनाने पर सहमति बनी है। इस फैसले से कांगडा और मंडी क्षेत्रों में राजनीतिक सन्तुलन बन जाता है। यह माना जा रहा है कि विधायक वीरभद्र को विधान सभा भंग करने का फैसला नही लेने देंगे। क्योंकि अभी उनके पास एक साल का कार्यकाल बचा हुआ है। जिसे वह खोना नही चाहेंगे। ऐसे में हाईकमान को भी पार्टी के बहुमत के फैसले को अधिमान देना होगा अन्यथा पार्टी के अन्दर बगावत हो जायेगी यह माना जा रहा है।

क्या नेता घोषित किये बिना भाजपा 50 का लक्ष्य प्राप्त कर पायेगी

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य घोषित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनायी गयी रणनीति के तहत ही हिलोपा का भाजपा में विलय हुआ है यह स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि इस विलय के बाद ही खुशीराम बालनाहटा, राकेश पठानिया, महन्त राय चौधरी, रूप सिंह ठाकुर और महेश्वर सिंह को कार्यसमिति में शामिल किया गया। कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने के लिये ही यह कदम उठाया गया है। बल्कि अब राजन सुशान्त और महेन्द्र सोफ्त को भी वापिस लाने के लिये संघ के स्तर पर प्रयास किये जाने की चर्चा है। पचास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाकर आक्रामकता अपनाने का प्रयास किया जायेगा। वैसे भाजपा का यह आरोप पत्र कितना आक्रामक होगा इसका पता तो 24 दिसम्बर को ही लगेगा जिस दिन यह सौंपा जायेगा। वैसे आरोप पत्रों को लेकर भाजपा की गंभीरता अब विश्वसनीय नही रही है। क्योंकि

जब से वीरभद्र ने उनके विरूद्ध चल रही सीबीआई, ईडी और आयकर जांच को भाजपा में धूमल, जेटली और अनुराग ठाकुर का प्रायोजित राजनीतिक उत्पीड़न करार देना प्रचारित किया है तब से भाजपा वीरभद्र के इस प्रकरण पर एक दम मौन हो गयी है। भाजपा के अन्दरूनी सूत्रों के मुताबिक इस मौन का कारण वीरभद्र के मामलों को उछालने से उन्हें सहानुभूति मिलना माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र मामलों पर भाजपा द्वारा करवाये गये सर्वे से सहानुभूति का गणित समाने आया है इतने गंभीर मामलों पर भी सहानुभूति का अर्थ है कि या तो भाजपा को स्वयं ही इन मामलों की पूरी समझ नहीं है या फिर वास्तव में ही यह प्रायोजित राजनीतिक उत्पीड़न ही है। यह दोनों ही स्थितियां भाजपा के लिये घातक हो सकती है। इस परिदृश्य में पचास का लक्ष्य केवल दावा होकर ही रह जाये यह भी हो सकता है। क्योंकि भाजपा अपने पहले सौंपे दोनों आरोप पत्रों को तो स्वयं ही भूल चुकी है फिर जनता के याद रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर यह तय है कि इस विधानसभा चुनाव का केन्द्र बिन्दु वीरभद्र के गिर्द ही घुमेगा।

वीरभद्र के संद्धर्भ में भाजपा का बंटवारा जग जाहिर है। शान्ता वीरभद्र एक दूसरे के कितने प्रशसंक है यह किसी से छिपा नही है। केन्द्रिय

शेष पृष्ठ 8 पर ....

राज्यपाल ने किया अन्तर्राष्ट्रीय लवी मेले का उद्घाटन

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला जिले के रामपुर में चार दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय लवी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाजों और परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध है और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि राज्य के

लोग अपने मेले तथा उत्सवों को बड़ी श्रद्धा और पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि मेले और उत्सवों की राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके पुरातन वैभव के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है और यह न केवल व्यापारिक गतिविधियों बल्कि पौराणिक परम्पराओं के लिए भी प्रसिद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भारत और तिब्बत के मध्य सदियों से प्रचलित एक महत्वपूर्ण व्यापार मेला है और अपनी तरह का एक गौरवशाली, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास और हिमाचल प्रदेश की विरासत का एक अनूठा उदाहरण है। आज भी यह मेला अपनी पूर्व परम्पराओं को संजोए हुए है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिला और राज्य के अन्य भागों से आए लोक कलाकार अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे और युवाओं में सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की महत्ताओं को संरक्षित करने के संदर्भ में अपनी छाप छोड़ जाएंगे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'देवभूमि' की सौंदर्यता को, आसपास को स्वच्छ रख कर और भी निखारा जा सकता है और इस दिशा सक्रिय स्वच्छता अभियानों को चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आज एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है और मानवता के लिए बहुमूल्य वातावरण बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के एक समान आंका जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने में अपना सहयोग देने का आग्रह किया, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग की विकास में महत्वूपर्ण व समान भूमिका रहती है।

राज्यपाल कहा कि महिलाओं को उचित व बराबर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने गिरते लिंग अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज के सभी वर्गो से भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लड़कियों का हर क्षेत्र में प्रदर्शन श्रेष्ठ है। उन्होंने मादक पदार्थो के सेवन की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की और युवाओं से ज्ञानवर्धन, सामजिक कार्य और मुख्यधारा की गतिविधियों में सम्मिलित होने का आग्रह किया।

आर्चाय देवव्रत ने लोगों से शून्य बजट आधारित खेती अपनाने का आग्रह किया और कहा कि रासायनिक खादों के अत्याधिक उपयोग से बीमारियां बढ़ रही है। उन्होंने विदेशी गायों के स्थान पर देशी गायों को पालने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि सीमित क्षेत्र में अधिक से अधिक पैदावार के लिए जैविक खेती को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अपनाने में किसानों की सहायता के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने आयोजकों की मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊनी कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं और यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ-साथ इन उत्पादों के प्रचार-प्रसार व बिक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

राज्यपाल ने 'किन्नौरी मार्किट' का भी शुभारम्भ किया और इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में गहरी रूचि दिखाई।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और समाज के कमजोर वर्ग के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। राज्यपाल के उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर चलाए गए पर्यावरण संरक्षण, गौ पालन, समानता, बेटी बचाओ, जैविक खेती इत्यादि प्रमुख मुद्दे है और यह हमारा सौभाग्य है कि इतने उच्च मूल्यों वाला महान व्यक्तित्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।

मुख्य संसदीय सचिव नन्द लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अनेक कार्य आरम्भ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लवी मेले की ऐतिहासिक महत्ता है, जो सदियों से वाणिज्यिक गतिविधियां को बढ़ावा दे रहा है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVIING TENDER

Sealed item rate tenders are herby invited /re-invited on form No. 6&8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/firms enlisted in H.P. P.W.D.in the appropriate class so as to reach in this office on or before 12.12.2016 to 10:30A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in The presence of intending contractors or their authorized representative. the tender form can be had from this office against cash payment (Non-Refundable) on 09.12.2016 upto 4:00 PM. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Name of work No. 1. Improvement of black spot on Khora Bira road km 0/0 to 5/0 (SH:- C/O R/wall at Rd 2/880 to 2/905) Estimated Cost 3,53,039/- Earnest Money 7,100/- time three Months 350/-

Name of work No. 2. A/R & M/O various roads under Chakomh Section (SH:- Repair of pot holes at various road & various Rds. Under Chakmoh section)) Estimated Cost 5,00151/- Earnest Money 10,000/- time three Months 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The Earnest Money in the Shape of National Saving certificate /Time deposit saving Account/FDR in any of the post office /National Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Basar must be accompanied with the application.
2. Conditional tenders and the tenders reserved without earnest money will out rightly be rejected.
3. The contractor shall accompany his enlistment/ renewal order with his application for obtaining the tender documents.
4. Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.
5. The work will be completed by the contractor within the stipulated period.
6. Tender forms will not be issued to those contractors who are not registered under HPGST Act 1988 & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained with aforesaid documents.
7. The contractor /firms are required to insert thee rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept /reject any overall tender.
8. The tender shall be only those contractors /firms who are found eligible suitable and competent.
9. The tender forms shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shall be duly evaluation by the technical evaluation committee.
10. Bituman for patch work /Pot holes repair shell be arranged by the contractor himself and contractor /firm having necessary documents past adequate experience shell be preferred.
11. Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shell not be issued tender form. . 12. Ones contractor should not have more works in hand at a time.
13. If **12.12.2016** happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00A.M.

Adv. No.-3026/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक की भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से राजभवन में नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक दीपक कुमार ने भेंट की तथा राज्यपाल को राज्य में नाबार्ड द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

उन्होंने आरआईडीएफ, किसानों के लिए रियायती दरों तथा समय पर पुनः वित्तीय सहायता, वित्तीय समावेशन, किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य विधायन, मौसम परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की परियोजना इत्यादि के माध्यम से ग्रामीण अधोसरंचना के विकास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2015-16 के दौरान नाबार्ड द्वारा राज्य को 500 करोड़ रुपये की आरआईडीएफ सहायता तथा 1090 करोड़ रुपये की पुनः वित्तीय सहायता सहित कुल 1696.54 करोड़ रुपये की सहायता राज्य सरकार को प्रदान की है।

राज्यपाल को इस अवसर पर मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड पर पुस्तिका, राज्य फोकस पेपर, आरआईडीएफ पर कॉफी टेबल बुक तथा सेक्टोरल पेपर्ज भी भेंट किए।

राज्यपाल ने नाबार्ड के विभिन्न विकास कदमों में गहरी रूचि ली और भविष्य में इसके लिए सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने नाबार्ड को सिक्किम की तर्ज पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने की सलाह दी।

इस अवसर पर नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

धर्मशाला में 18 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा 24 कुंडीय महायज्ञ एवं लोक जागरण

शिमला/शैल। गायत्री परिवार युग निर्माण योजना मथुरा के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के सुक्ष्म संरक्षण में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिवार ट्रस्ट जिला कांगड़ा द्वारा 18 से 21 नवंबर तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में 24 कुंडीय महायज्ञ एवं लोक जागरण सम्मेलन, गायत्री महायज्ञ व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। शांतिकुंज हरिद्वार के विद्वानों द्वारा युग संगीत, प्रवचनों और यज्ञीय कर्म कांडों के माध्यम से गायत्री मंत्र और यज्ञ के दार्शनिक और वैज्ञानिक स्वरूप पर उद्बोधन किया जाएगा। 18 नवंबर को दोपहर 2 से 4 बजे तक पुलिस ग्राउंड से भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ होगा तथा 5 से 7 बजे तक संगीत संध्या आयोजित की जाएगी। 19 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक ध्यान व प्रागेय योग करवाया जाएगा तथा 9 से 12 बजे तक गायत्री महायज्ञ एवं जन्मदिवस संस्कार पूजन (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) अभियान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रवचन से 2 से 5 बजे तक होगा। 20 नवंबर को शाम 6 से 8 बजे तक दीप यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। 21 नवंबर को दोपहर गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति डाल कर विश्व शांति व मानव कल्याण की कामना की जाएगी।

24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं लोक जागरण प्रयोजन में भागीदार बन कर श्रेय व सुभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।

राज्यपाल का अध्यापकों से समर्पण भाव से कार्य करने का आग्रह

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि युवा देश की सम्पति हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिये करना चाहिए। अभिभावक व शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण तथा समाज में अपने लिए एक जगह बनाने के लिए उन्हें सक्षम करने में मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं।

राज्यपाल दिल्ली के डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारका के वार्षिक समारोह 'सियोना' में बोल रहे थे।

उन्होंने शिक्षक समुदाय से युवा पीढ़ी की नियति को आकार देने में अत्यन्त समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने आप को राष्ट्र सम्पति के रूप में साबित करना चाहिए तभी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि अनुशासन, देश प्रेम, सेवा भाव, अध्यापकों व बड़ों का सम्मान करना जैसे मूल्य पाठयक्रम में होने चाहिए, इनके बिना शिक्षा अधूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी समृद्ध संस्कृति तथा गौरवमयी इतिहास के बारे जानकारी दी जानी चाहिए और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव करना भी सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए, जिसमें ज्ञान के साथ-साथ जीवन की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना भी सिखाना चाहिए जिसे सुनिश्चित बनाना अध्यापकों की जिम्मेवारी है।

आचार्य देवव्रत ने द्वारा मूल्य आधारित गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये डीएवी संस्थानों की सराहना की। उन्होंने स्कूल प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की पहल के लिए उन्हें बधाई दी, जो विद्यार्थियों को सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने पाठयक्रम में तकनीकी के साथ वैदिक ज्ञान को शामिल करने के प्रयासों के लिये भी शिक्षकों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि वेद ज्ञान, प्रज्ञता एवं विद्या के असीम साधन हैं और युवाओं को इनकी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वेद ज्ञान को विश्वभर में स्वीकार किया गया है। उन्होंने हमारे देश की गौरवमीय परम्पराओं एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी युवा पीढ़ी को देने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनमें गौरव एवं देशभक्ति की भावना को विकसित हो सके।

ऋषि दयानंद के योगदान की सराहना करते हुए आचार्य देवव्रत ने कहा कि उन्होंने वेदों का प्रचार करके न केवल हमारी गौरवमयी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है, बल्कि आर्य समाज के माध्यम से समाज में व्यापत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की नीव भी रखी है।

सरकार के चार साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी 25 दिसम्बर को महारैली

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के चार साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मण्डी के पड्डल मैदान में 25 दिसम्बर, 2016 को एक 'महारैली' का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख तथा यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इस अवसर पर आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को दर्शाने के लिए 15 से 31 दिसम्बर, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए मोबाईल, पब्लिसिटी वाहन, एलईडी स्क्रीन, ध्वनि प्रसार प्रणाली, प्रदर्शनी पैनल इत्यादि भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी वाहन प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष प्रचार अभियान में संचार के सभी साधनों का उपयोग सुनिश्चित बनाया जाएगा ताकि सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंच सके।

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के जरिए बहु प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 से 31 दिसम्बर, 2016 तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा विशेष प्रसार अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें राज्य में विभिन्न सम्मेलन, संगीत एवं नाट्य प्रदर्शन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के चार साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा 17 दिसम्बर, 2016 को ओकओवर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पब्लिसिटी स्टाल स्थापित किए जाएंगे।

अग्निहोत्री ने कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज्य सरकार की सफलता की कहानियों पर आधारित लघु फिल्म व वृत्त चित्र भी तैयार करेगा और यह मोबाइल वैनों व स्थानीय केवल आप्रेटरों के माध्यम से दर्शाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए निश्चित स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिक न्यूज डिस्प्ले बोर्ड भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को दर्शाने के लिए प्रकाशन सामग्री जैसे बुकलैट, फोल्डर, पैम्फलेट तथा अन्य सामग्री भी जनमानस में वितरित करेगा।

विमुद्रीकरण के निर्णय का किया स्वागत: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मण्डी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर किसी की कल्पना से परे बढ़ चुका है, और इस पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय का स्वागत किया। हालांकि, प्रधानमंत्री का अचानक निर्णय जल्दबाजी में उठाया गया कदम प्रतीत होता है, बेशक यह एक साहसिक कदम है। उन्होंने कहा कि किसानों, छोटे व्यवसायियों व दुकानदारों, दिहाड़ीदारों तथा बहुत से उन लोगों, जिनके पास कठिन परिश्रम से अर्जित किया धन है, के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा नोटों के विमुद्रीकरण से पूर्व आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिए थे। अचानक आया यह निर्णय उन लोगों को, जिनके शादी समारोह चल रहे हैं, किसानों तथा छोटे व्यवसायियों, जिन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता है, के लिए एक बड़ा धक्का है।

मुख्यमंत्री ने कहा यद्यपि वह साहसिक निर्णय तथा काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं ताकि भ्रष्टाचार के विरूध लड़ा जा सके।

उन्होंने मण्डी बस दुर्घटना, जिसमें 17 लोगों ने अपनी बहुमूल्य जानें गवाई, के घायलों का कुशलक्षेम पूछने के लिए आंचलिक अस्पताल का दौरा भी किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार राज्य में सड़कों तथा ब्लैक स्पॉट की हालत सुधारने का कार्य कर रही है।

परिवहन निगम के कर्मचारियों/पेंशनरों को जारी किए जाएंगे 15 करोड़:बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को उनकी पेंशन व अन्य लम्बित देय लाभ प्रदान करने के लिये एक सप्ताह के भीतर 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। यह जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि इस राशि में से 817 लाख रुपये निगम के 4795 कर्मचारियों को सितम्बर माह की पेंशन प्रदान करने के लिये जारी किए जाएंगें।

बाली ने कहा कि 17 करोड़ रुपये की राशि 8 माह पुराने एनएओ/ओटीए देय का भुगतान करने के लिये पहले ही जून, 2016 के दौरान जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एनएओ/ओटीए के दो माह के लंबित भुगतान में से अगस्त, 2014 की 230 लाख रुपये की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इस राशि में से 180 लाख रुपये सेवानिवृत कर्मचारियों का अगस्त तथा सितम्बर, 2015 का अवकाश के बदले लंबित वेतन का भुगतान करने के लिये जारी किए जाएंगें। इससे 59 पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा। बाली ने कहा कि जुलाई तथा अगस्त, 2015 की लंबित ग्रेच्युटि (उपदान) की अदायगी के लिये 244.23 लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी जिससे 53 पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि चार मृत्यु के मामलों में मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान (डीसीआरजी) का भुगतान करने के लिये 29 लाख रुपये जारी किए जाएंगें। परिवहन मंत्री ने कहा कि हि.प्र. पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने के लिये इन सभी अदायगियां के लिये राशि 20 नवम्बर, 2016 से पूर्व जारी कर दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थानों के रिक्त पदों के उप-चुनाव 11 दिसम्बर को

शिमला/शैल। हि.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए उप-चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 90 पद रिक्त हैं, जिनमें प्रधान के 9 पद, उप प्रधान के 3 पद, पंचायत समिति व सदस्य ग्राम पंचायत के लगभग 78 पद शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग इन रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 15 नवम्बर को उप-चुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित करेगा। नामांकन 25, 26 तथा 28 नवम्बर, 2016 को प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन की समीक्षा 29 नवम्बर, 2016 को की जाएगी। नामांकन पहली दिसम्बर, 2016 को वापिस लिए जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 11 दिसम्बर, 2016 को प्रात: 7 बजे से सायं 3 बजे तक होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रधान, उप-प्रधान व सदस्यों के लिए मतों की गणना मतदान के तुरन्त बाद की जाएगी, जबकि पंचायत समितियों के लिए मतों की गणना 12 दिसम्बर, 2016 को होगी। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में उप-चुनाव होने हैं, में आचार संहिता लागू हो चुकी है।

प्रवक्ता ने कहा कि इन चुनावों में 1.1.2016 को अहर्ता तिथि मानते हुए अद्यतन की गई मतदाता सूचियां प्रयोग की जाएंगी। यदि कोई मतदाता 1.1.2016 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो तो वह अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाने के लिऐ नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 9 दिन पूर्व संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार नाम अथवा किसी प्रविष्टि में शुद्धि के लिये भी आवेदन किया जा सकता है।

आपदा पर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिये अति.संवेदनशील है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा चिन्हित कुल 33 आपदाओं में से राज्य 25 प्रकार की आपदाओं की चपेट में है। इनमें बहुतायत में घटित होने वाली आपदाओं में भूकंप, भू.स्खलन, ल्हासे गिरना, ग्लेशियर तथा बाढ़ प्रमुख हैं। इन आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता के दृष्टिगत राज्य सरकार ने आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों में सक्रिय कारवाई को मजबूती प्रदान करने तथा सुविधा प्रदान करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया है। राजस्व मंत्री इसके सदस्य जबकि मुख्य सचिव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसी प्रकार राज्य के समस्त 12 ज़िलों में भी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबन्धन को लेकर देश में प्रतिमान विस्थापन यानि बड़ा बदलाव आया है। आपदा के उपरांत राहत प्रदान करने के पुराने दृष्टिकोण के स्थान पर राज्य सरकार ने आपदा पूर्व तैयारियों, शमन तथा जोखिम कम करने के दृष्टिकोण को अपनाया है। आपदा की तैयारियों, प्रतिक्रिया, पुन: प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ तथा पुन: बहाली के सतत् प्रयास पर बल दिया गया है।

राज्य सरकार ने खतरों, अति संवेदनशीलता तथा जोखिम आंकलन को लेकर एक व्यापक एटलस (एचवीआरए) तैयार किया है और हिमाचल एटलस तैयार करने वाला देश का मात्र हिमालयी राज्य है। एचवीआरए राज्य के 12 ज़िलों तथा 78 विकास खण्डों को कवर करता है तथा इसे आपदा जोखिम स्तरों के परिमाण तथा आपदा जोखिम कम करने में मागदर्शन करने वाले संबंधित आकस्मिक कारकों का आंकलन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

आपदा के समय सहायता सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक बटालियन कांगड़ा जिले के नूरपुर में स्थापित की है। आपदा से निपटने के लिये स्थापित इस बटालियन के लिये हिमाचल एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से भूमि क्रय कर आवासों का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है जिसके लिये पुलिस विभाग की तृतीय भारतीय रिजर्व वाहिनी पण्डोह तथा पीटीसी डरोह में एसडीआरएफ कंपनियों को प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान करने के लिये पर्याप्त धनराशि जारी की गई है।

आपदा प्रबन्धन को लेकर राज्य पदाधिकारियों सामान्य समुदाय तथा विशेष तौर पर युवाओं को राज्य तथा जिला स्तर पर समय.समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिमला स्थित हिप्पा, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियलरग एलाग्रड स्पोर्टस तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान नई दिल्ली में प्रदान किए जा रहे हैं।

हिमाचल ने राज्य आपदा प्राधिकरण की सहायता के लिये इसके कार्यो का प्रदर्शन, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई का समन्वय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना के लिये राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है।भारत सरकार ने 14वें वित्तायोग अनुदान के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों के लिये 1304 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जिसमें क्षमता निर्माण की 5 प्रतिशत की राशि भी शामिल है।

शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में आपदा जागरूकता संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के कांगड़ा और कुल्लू जिलों में राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम पर एक पायलट परियोजना क्रियान्वित की गई है। इसके लिये 1.68 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम की अन्य परियोजना एससीईआरटी सोलन तथा जीसीटीई धर्मशाला के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के लिये कार्यान्वित की जा रही है।

उपायुक्त द्वारा बैंक अधिकारियों से सभी बैंक शाखाओं में पर्याप्त पैसा उपलब्ध करवाने के निर्देश

शिमला/शैल। उपायुक्त शिमला रोहन चन्द ठाकुर ने बैंक अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंक शाखाओं विशेष तौर पर ग्रामीण व दूरवर्ती क्षेत्रों में पैसों की उपलब्धता बारे जानकारी हासिल की।

उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि वे जिला की सभी बैंक शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में पैसा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनायें । उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और यूको बैंक से संबध हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं में पैसा भेजना सुनिश्चित बनायें। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश आनंद तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य के सबसे ऊँचे तिरंगे को समर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनके निजी आवास हॉलीलॉज से हमीरपुर में स्थापित राज्य के सबसे ऊँचे 133 फुट राष्ट्रीय स्मारक (तिरंगा) को ऑनलाइन समर्पित किया। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी हमीरपुर में इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने प्लैक का अनावरण किया।

हमीरपुर के उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि यह राज्य का सबसे ऊँचा झंडा है। उन्होंने कहा कि स्मारक जिले के उन शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है।

पूंजी अपने – आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी ना किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। ....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

प्रशंसा और सहयोग के हकदार है मोदी

प्रधानमन्त्री मोदी ने एक साहसिक फैंसला लेकर एक हजार और पांच सौ के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त किया जाने की घोषणा करके काले धन के खिलाफ एक एक प्रभावी कदम उठाया है। इसके लिये मोदी और उनकी टीम बधाई की पात्र है। इस फैंसले के लिये देश की जनता उन्हे लम्बे समय तक याद रखेगी इसमें कोई दो राय नही हो सकती क्योंकि देश के अन्दर एक लम्बे वक्त से काले धन को लेकर बहस चली आ रही थी। कई बार काले धन के आंकडे उछाले जाते रहे हैं। स्वामी रामदेव ने काले धन को लेकर आन्दोलन तक छेड़ने का प्रयास किया था। 2014 के लोक सभा चुनावों से पूर्व मोदी ने वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आते है तो सौ दिन के भीतर देश के बाहर रखे गये धन को वापिस लाया जायेगा। इस धन के वापिस आने से प्रत्येक भारतीय के खाते में पन्द्रह लाख आने का दावा किया था। लेकिन इस वायदे को पूरा करना आसान नहीं था। विदेशों से काला धन वापिस लाने के लिये एक लम्बी और जटिल कानूनी प्रक्रिया वांछित थी। इस पक्रिया पर यू पी ए सरकार के समय में भी कदम उठाये गये थे अब वित्त मन्त्री अरूण जेटली ने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है और कई देशों से इस संबंध में समझौते भी हस्ताक्षरित हो चुके हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत वांछित परिणाम आने में समय लगना स्वभाविक है। इस समय लगने की सच्चाई को जानने समझने के बावजूद प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख आने के दावे वायदे को मोदी सरकार की आलोचना और असफलता का हथियार बनाया गया।

जहां एक और काला धन समस्या थी वहीं दूसरी और बढ़ती आंतकवादी घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही थी इस पर भी मोदी की आलोचना होनी शुरू हो गयी थी। सवाल किये जाने लगे थे कि 56 इंच का सीना अब कहां है इसका जवाब भी मोदी ने आतंकी बेस कैंपो पर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया। भले ही वन रैंक वन पैंशन का मुद्दा अभी पूरी तरह हल नहीं हो पाया है और पूर्व सैनिक रामकिशन की आत्महत्या के बाद इस पर राजनैतिक बवाल भी खड़ा हो गया है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और वन रैंक वन पैंशन को अलग – अलग करके देखना होगा। इसलिए हजार और पांच सौ के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त करना तथा सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी प्रशंसा और सहयोग के हकदार हैं।

काला धन जितना देश के बाहर है उससे कहीं अधिक देश के भीतर हैं आज रियल इस्टेट और गोल्ड मार्किट में काला धन स्पष्ट देखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी बिल्डर फ्लैट/मकान /प्लाट की घोषित कीमत की सारी अदायगी चैक से नहीं लेता है और जो अदायगी चैक से नही होती है वह काला धन है। सारी घूसखोरी कालाधन है। सारा चुनाव काले धन के सिर पर लड़ा जाता है। ठेकेदारी में काले धन की बड़ी भूमिका है। कुल मिलाकर आज कालाधन दैनिक क्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया है। आंतकवाद काले धन के बिना एक दिन नहीं टिक सकता। नशे का सारा कारोबार कालेधन का ही पर्याय है। कोई भी गैर कानूनी काम काले धन के बिना नहीं चल सकता। बेरोजगारी, मंहगाई और आंतकवाद तथा भ्रष्टाचार का आधार यह काला धन ही है। इस काले धन से निपटने के लिये करंसी में इस तरह का फैंसला लिये जाने के अतिरिक्त और कोई कारगार विकल्प ही नही। क्योंकि कोई भी धन तभी काला धन बनता है जब उसका स्त्रोत वैध न हो। ऐसे धन का सबसे ज्यादा बेनामी संपत्तियों में होता है। मोदी सरकार ने इसी वर्ष कालेधन और बेनामी संपत्तियों को वैध करने के लिये आयकर विभाग के माध्यम से मुहिम चलाई। अब इस योजना के समाप्त होते ही हजार और पांच सौ के नोटों का चलन रोक दिया। सरकार के इन दोनो कदमों के एक साथ आने से सरकार की नीयत पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। हर आदमी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहा है। भले ही उसे पहले दिनों व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इस कदम के बाद चुनावों को भी कालेधन से मुक्त किये जाने की योजना आनी चाहिए। यदि चुनाव कालेधन से मुक्त हो जाये तो लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जायेंगी यह तय है।

राज्य में सतत् शहरी विकास सुनिश्चित बनाने में हिमुडा का अहम् योगदान

नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित बनाने तथा आर्थिक एवं पर्यावरण प्रभावों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार भविष्यवादी योजनाओं के साथ स्मार्ट एकीकृत शहरों के विकास के साथ – साथ मौजूदा मध्यम आकार के उपनगरों के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्वार को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

शहरी क्षेत्रों के तेजी से होते विस्तार के कारण आवासों की मांग निरन्तर बढ़ रही है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य में आवासीय कालोनियों की व्यवस्थित योजना एवं विकास सुनिश्चित बना रही है। सरकार न केवल लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है, लेकिन सतत् शहरी विकास को भी सुनिश्चित बना रही है। गैर प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताएं भी पूरी हों। नए उपनगरों की गतिशीलता एवं जुड़ाव मौजूदा शहरों के साथ करने पर बल दिया जा रहा है।

राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से आवासीय एवं विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। आवासीय एवं विकास योजनाओं में भूमि विकास योजना, शहर, नगर अथवा ग्राम विकास योजना, औद्योगिक क्षेत्र विकास मनोरंजन केन्द्र, अस्पतालों, पार्कों, शिक्षण संस्थानों तथा अन्य सम्बद्ध शहरी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना सिंगापुर के विशेषज्ञों की सहायता से क्रियान्वित की जाएगी, जिसके लिए अंतरिम अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

हिमुडा ने अब आवासीय एवं व्यावसायिक परिसम्पत्तियों के विकास एवं आवंटन की पुरानी संरचना से हट कर निर्णय लिया है। हिमुडा शॉपिंग

हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय भौगोलिक परिक्षेत्र है, जहां मकानों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता एक प्रमुख समस्या है। मौजूदा शहरों के केन्द्रीय क्षेत्रों में भूमि शेष नहीं बची है तथा अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा अधोसंरचना पर्याप्त नहीं है, जबकि आवश्यक बुनियादी सुविधाओं सहित आवासों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। शहरों में आबादी का प्रवासन निरंतर बढ़ रहा है और ऐसा कतई नहीं लगता कि यह प्रवासन कम होगा। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने गुणात्मक एवं परिमाणात्मक 'एकीकृत उपनगर बसाने' की अवधारणा को अपनाया है।

ये उपनगर शिमला, सोलन, कसौली, मण्डी, हमीरपुर तथा धर्मशाला शहरों के समीप विकसित किए जा रहे हैं तथा इन परियोजनाओं के विकास में यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि इनसे न केवल राज्य के लोगों, बल्कि बाहरी लोगों एवं योजना, पर्यटन योजना तथा अधोसंरचनात्मक योजना शामिल हैं।

हिमुडा ने अभी तक विभिन्न स्थानों पर 73 आवासीय कालोनियां तथा 17229 आवास/फ्लैट/प्लाटों का निर्माण किया हैं। शिमला, नाहन, धर्मशाला तथा कुल्लू में 146 और फ्लैटों का निर्माण तथा 181 प्लाटों का विकास प्रगति पर है। शील, धर्मपुल, त्रिलोकपुर तथा मोगीनानंद में 301 प्लाटों व 400 फ्लैटों की चार नई आवासीय कालोनियां तथा शिमला में एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण प्रगति पर है।

राज्य की राजधानी में भीड़ – भाड़ को कम करने के लिए शिमला के समीप जाठिया देवी में एक एकीकृत उपनगर की स्थापना के लिए निजी मालिकों से 206535 वर्गमीटर भूमि की खरीद की गई है, जबकि 116334 वर्गमीटर सरकारी भूमि पहले ही चिन्हित कर ली गई है। इस नए शहर में लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक परिवहन, सामुदायिक केन्द्र, बस अड्डा, मॉल, लग्जरी होटलों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, विश्राम स्थलों तथा मनोरंजन सुविधा जैसे रियल एस्टेट संघटकों सहित गुणात्मक शहरी अधोसंरचना के सृजन पर बल दे रहा है।

कोर रियल एस्टेट परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड के माध्यम से निवेश लाने तथा तय समय सीमा के भीतर इन परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित बनाने के लिए महत्वकांक्षी नीति अपना रहा है।

राज्य के शहरी एवं नगर नियोजन विभाग ने निर्माणकर्ताओं अथवा विकासकों की सुविधा के लिए मानदण्डों को सरल बनाया है और हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन स्वीकृतियां प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी प्रकार, सभी आवेदनों को एक स्थान पर निपटाने के लिए मोबाइल ऐप भी शुरू की गई है।

भ्रष्टाचार से लड़ाई में जन भागीदारी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 का विषय "ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से लड़ाई में जन भागीदारी" है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहल के अंतर्गत मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पीछे मुख्य विचार यह है कि आयोग को महसूस हुआ कि भारत जैसे विशाल देश में हम जन भागीदारी के बिना ईमानदारी को प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। 'एन. विट्ठल'

ईमानदारी और भ्रष्टाचार क्या है

ईमानदारी बुनियादी तौर पर वह स्थिति है, जो पूरी तरह से सुसंगत होती है और कोई अलगाव नहीं करती है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो ईमानदारी की मतलब सच्चाई या सरलता से है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को ईमानदारी के जिस मुद्दे का सामना करना पड़ता है, उसके तीन विभिन्न दृष्टिकोण हैं। एक ईमानदारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा, दूसरी वित्तीय सत्यनिष्ठा और तीसरी नैतिक या नीतिपरक सत्यनिष्ठा है।

विश्व बैंक द्वारा वर्णित भ्रष्टाचार शब्द की परिभाषा 'सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए हो' है। जहां तक सख्त कानूनी पहली की बात है, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 फैसला लेने के वास्ते एक मामला सामने आने पर अदालत के लिए निष्पक्ष स्थिति का वर्णन करता है, चाहे भ्रष्ट आचरण हुआ हो या नहीं हुआ हो। इस कागज में हमारे विश्लेषण के लिए निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय के इस्तेमाल की विश्व बैंक की परिभाषा तुलनात्मक रूप से काफी सटीक और व्यापक है और समझने में आसान है।

जन भागीदारी

हम अब हमारे देश और भारत सरकार के संदर्भ में 'ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से लड़ाई में जन भागीदारी' का परीक्षण कर सकते हैं। वह भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ही थे, जिन्होंने सुझाव दिया कि यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग को वर्ष में एक सप्ताह को 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के तौर पर मनाना चाहिए। इससे सभी सरकारी संगठनों में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन इस पूरे मुद्दे के जनता बीच जाने से इसके कई गुना असर होंगे।

शेषन ने जैसी कल्पना की थी, आज वह उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित हो गया है और हम बीते दो दशकों के इतिहास पर गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि आज का युवा ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो सुशासन की अनिवार्य शर्त भी है।

एक प्रकार से सतर्कता जागरूकता सप्ताह ने गुणात्मक चक्र की गति स्थापित करती है, जिसका मतलब एक अच्छे घटनाक्रम के बाद आने वाले दूसरे घटनाक्रम से है। यह उचित होगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर 2000 के बाद से हमारे देश में सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए। 2000 में ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई थी।

इसकी शुरुआत के बाद से केंद्रीय सतर्कता आयोग में कई बदलाव सामने आए और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार से लड़ाई हकीकत के तौर पर सामने आई, जिसके लिए सार्वजनिक भागीदारी भी संभव हो सकी।

आरटीआई कानून का प्रादुर्भाव

यह विडंबना ही है कि मौजूदा दौर की शुरुआत में राजस्थान में जन भागीदारी प्रशासन में विश्वसनीयता और भ्रष्टाचार रोकने की मांग कर रही थी, जो देश के सबसे ज्यादा पिछड़े राज्यों में से एक है। हमारे देश के विभिन्न राज्य विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं और भले ही भारत की सांस्कृतिक सत्यनिष्ठा कायम है, वहीं हम बहु जातीय, बहुभाषीय और बहु गति वाले देश हैं। जब हम कई क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई पिछड़े राज्यों की तुलना में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में बड़ा अंतर है।

यह राजस्थान था जब एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय जो भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा भी रही हैं, की अगुआई वाले एक गैर सरकारी संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) ने गांवों के लोगों के बीच जागरूकता फैलाई कि उन्हें जानना चाहिए कि गांवों के विकास के लिए पंचायतों के मिलने वाला भारी धन का सही इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने विषय को रेखांकित किया कि **कर राजस्व 'हमारा धन है, हमें खाता दिखाइए कि हमारा पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है।' 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब'** ही वह विषय था जिस पर राजस्थान के गांवों में शांति और व्यवस्थित तरीके से काम कर सकीं। यह एक प्रभावशाली आंदोलन में तब्दील हो गया, जो आखिरकार 2005 में सूचना के अधिकार कानून के रूप में सामने आया।

यह कानून क्रांतिकारी था। यह उस अवधारणा के बिल्कुल उलट था, जिसके तहत राज्य अभी तक शासन कर रहे थे, विशेष रूप से औपनिवेश काल के बाद से। अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं था, जिससे नागरिकों को भरोसे में लिया जा सके और सरकार बता सके कि उनके कर के रूप में दिए गए धन को कैसे खर्च किया जा रहा है। आरटीआई एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हुआ, क्योंकि इससे जन भागीदारी सुनिश्चित हुई जिससे जागरूकता फैसला और सुनिश्चित हुआ कि सरकारी व्यवस्था में भी पारदर्शिता लाई जा सकती है और सरकार को भी विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

2010 में अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र के रालेगांव शहर के गांव में तीन दशकों से ज्यादा वक्त से सक्रिय रहे हैं, लोकप्रिय आंदोलन इंडिया अंगेस्ट करप्शन (आईएसी) के नेता के तौर पर सामने आए। इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि यह आजादी के बाद का दूसरा बड़ा आंदोलन था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के दम पर इसे खासी सफलता मिली।

इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के विकास जो आज एससीएम (सोशल, क्लाउड, एनालिटिकल, मोबाइल) संचार के विकास वाले क्षेत्र हैं, ने वर्चुअली हर नागरिक और मतदाता के हाथ में बड़ी ताकत दे दी है, जिससे वे सूचनाएं पा सकते हैं और अपने विचारों को फैला सकते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं। इसका असर विशेषकर पिछड़े इलाकों में ज्यादा दिखा है, जहां भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया जा सका। हालांकि मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच ने लोगों को खासा सशक्त बना दिया है।

हमारे जैसे देश में, विशेषकर पिछले दशक के दौरान ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी बढ़ी है और इसके आधार पर राजनीतिक एजेंडा और चुनावी मुद्दे तय हुए हैं। 2014 के चुनाव ने काफी हद तक सिविल सोसायटी आंदोलनों और कई घोटालों की मीडिया कवरेज के आधार पर ही आकार लिया। इसलिए इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार से लड़ाई में जन भागीदारी विषय उचित ही है।

यह एक व्यापक अवलोकन हो सकता है। बीते दो दशक और उससे ज्यादा वक्त से हमारा अनुभव हमें बताता है कि जन भागीदारी के कई पहलू हैं और एक स्पष्ट है कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है और हमें निष्पक्ष रहना है। वास्तव में बीते कुछ साल में सामने आए भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन जन भागीदारी के तरीकों के कुछ नकारात्मक असर पर भी सामने आते दिखते हैं। इस संदर्भ में मीडिया की भूमिका खासी अहम होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भ्रष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की कमी के मुद्दे को उठाने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि इसके पीछे जनता की सेवा का काल्पनिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ अवसरों पर इसके व्यापक व्यावसायिक हित भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में टेलीविजन रेटिंग अंकों को लेकर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इसलिए सत्यता के पीछे छूटने की संभावना बनी रहती है।

इन सबके साथ हमें हमारी न्यायिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका की प्रशंसा की जानी चाहिए, जो दोषी को जेल भेजने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली एजेंसियों के लिए मानकों को बरकरार रखने में सक्षम है।

वास्तव में कई घोटाले जिन्होंने हाल के दौर में पिछली सरकारों की छवि खराब की है, निजी लाभ के लिए अधिकारों के दुरुपयोग से ही संभव हुए हैं, जो मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जागरूकता से ही सामने आ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता सबसे बड़ा हथियार है। हमारे पास अब लोकपाल कानून है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कैसे प्रभावी होगा, क्योंकि सत्यनिष्ठा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है।

जैसे कि हमने देखा है कि इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह में लेखक के तौर पर मैं एक अहम पहलू पर जोर देता हूं। यह पहलू है कि अब हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायी नेतृत्व है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन से ही सुशासन पर जोर दिया। उनके हर कदम से जाहिर होता है कि उनकी सोच व्यापक है। हम सभी देश के सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री रहने के दिनों से उठाए गए कदमों और उनके प्रचार के तरीकों से जाहिर होता है कि वह जानते हैं कि अनंत सतर्कता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। उनके नेतृत्व में हम अपनी नैतिक सांस्कृतिक जड़ों से मिलने वाली प्रेरणा के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक बनने की राह पर हैं।

पसूका

नीतियों एवं प्रसार में अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं अधिकारी:आर.एस.नेगी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक आर एस नेगी ने विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो सरकार की नीतियों व खूबियों को जनता तक पहुंचाने के मामले में न्यू मीडिया को नजरअंदाज न करें। बेहतर सूचना प्रबन्धन एवं जन सम्पर्क के लिए सोशल मीडिया के प्रभाव की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने ने कहा कि जन सम्पर्क अधिकारियों को मीडिया के बदलते

तौर तरीकों के साथ चलने के लिए आधुनिक संचार कौशल के साथ अपने आप को अद्यतन बनाना चाहिए।

मौजूदा दौर में मीडिया में तेजी से हो रहे बदलाव के चलते नवीन मीडिया के बेहतर एवं प्रभावी उपयोग पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों तथा अन्य फील्ड कर्मियों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि वे अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके। वह यहां सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग आगामी माह एक विशेष प्रचार अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेवारियों का अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकें। उन्होंने प्रभावी जन सम्पर्क के लिए विश्लेषण एवं सूझबूझ पर आधारित जानकारी, जो संस्थान के प्रति लोगों के रवैये को प्रभावित करती हैं, की आवश्यकता पर बल दिया।

निदेशक ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में मल्टी-मीडिया वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मल्टीमीडिया वाहनों को ध्वनि प्रसार यंत्र एलडीईटीवीए प्रचार सामग्री इत्यादि से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारियों को प्रचार वाहन के प्रस्तावित रूट के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा ताकि इसका अधिक से अधिक प्रभाव सुनिश्चित बनाया जा सके।

नेगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जिला अधिकारियों को संबंधित जिलों में मंत्रियों अथवा जन प्रतिनिधियों की नियमित प्रेस वार्ताएं आयोजित करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने सम्बन्धित जिलों में सफलता की कहानियों का पता लगाकर इनका समाचार पत्रों तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार व प्रसार करना चाहिए। समाचार पत्रों में उपयुक्त स्पेस प्रबन्धन पर बल देते हुए नेगी ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों को नियमित तौर पर समाचारों तथा मीडिया में आने वाले विचारों पर निगरानी रखनी चाहिए और मीडिया की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सकारात्मक लेख उपलब्ध करवाने चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपयुक्त फीडबैक उपलब्ध करवाने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सरकार एवं आम जनमानस के मध्य बेहतर ताल-मेल स्थापित करने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार को उचित कदम उठाने में भी मददगार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न नीतियों एवं निर्णयों के सम्बन्ध में आम जनमानस के दृष्टिकोण एवं विचारों को बदलने में जन सम्पर्क अधिकारियों की अहम भूमिका है।

नेगी ने कहा कि सभी प्रकार के आधुनिक मीडिया के पर्याप्त उपयोग के साथ-साथ विभाग को पारम्परिक लोक मीडिया दलों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग की गीत एवं नाटय इकाइयों को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य के दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को बेहतर जन सम्पर्क के लिए पत्रकारों के साथ व्यावसायिक एवं निजी सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

सहकारी बैंक समेत प्रदेश में आधे से ज्यादा बैंकों के ATM बंद

शिमला/शैल। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में दो दो हजार रुपए के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समेत सभी बैंकों के आधे से ज्यादा एटीएम या तो बंद है या फिर उनमें पैसे नही है। प्रदेश सहकारी बैंक के शिमला में ही पिछले तीन दिनों से एटीएम नहीं चल रहे । उनमें शटर गिराया हुआ है।

बैंकों में नोट बदलने व पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा हैरान प्रदेश के सहकारी बैंक ने किया है। राजधानी शिमला में ही जहां बैंक का मुख्यालय भी हैं, वहीं पर एटीएम के शटर गिराए हुए है। ये एटीएम पिछले तीन दिनों से बंद है। देश के बड़े बैंक एसबीआई के प्रदेश व शहर में स्थित एमटीएम का भी यही हाल है। या तो उनमें से अधिकांश बंद पड़े हैं या उनमें पैसें नहीं है। इसके अलावा जिनमें पैसे हैं भी वहां भी लंबी कतारें लगी है।

राजधानी शिमला में लोगों की परेशानियों को देखते हुए डीसी रोहन चंद ठाकुर ने बैंकर्स को निर्देश भी दिए। चूंकि पैसे केंद्र सरकार/केंद्रीय बैंक की ओर से भेजे जाने हैं ऐसे में डीसी को नही सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नही है।

बहरहाल, प्रदेश में जहां लोगों को दो-दो हजार रुपए के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है वही काले धन को सफेद करने के भी कई नायाब तरीके निकाले जा रहे है। कोई प्रवासी मजदूरों का सहारा ले रहा है तो कोई रिश्तेदारों व कम पैसों वालों से जुगाड़ भिड़ा रहा है। विभाग की ओर से जानकारियां भी ली जा रही है। उधर, आयकर विभाग की ओर से लगातार सभी बैंकों पर निगाह रखी जा रही है।अपर शिमला में बैंकों की शाखाओं पर खास निगाह रखी जा रही है। इनकम विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई तभी से यहां पर कई कुछ हुआ है।

CUHP में ABVP कार्यकारिणी गठित, परमार अध्यक्ष, छात्र एक भी नहीं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई कार्यकारणी का गठन किया है। इसमें सभी पदों पर नेतृत्व की जिम्मेदारी छात्रों को दी गई हैं जबकि छात्राओं की भागीदारी नदारद रही। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर नज़र डालें तो यहां पर लड़कियों का पलड़ा भारी है, उनकी संख्या लड़कों से अधिक है। यहां पर अगर पूर्व में हुए छात्र संघ के चुनावों पर नज़र डाली जाए तो एबीवीपी का ही पलड़ा भारी रहा है।

कार्यकरणी गठन में विद्यार्थी परिषद

विश्वविद्यालय में एबीवीपी की गतिविधियों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का जिम्मा साहिल परमार को अध्यक्ष बना कर उनको सौंपा गया है। परमार विवि से एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहे सुमित धीमान को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष के पद के लिए चार छात्रों, पंकज, सौरव, मनीष और नरेन्द्र को सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सहसचिव का दायित्व संस्कृत विभाग के रोहित ठाकुर, अजय विशाल और विशाल को दिया गया। नई कार्यकारणी के गठन के लिए हुई इस बैठक में विद्यार्थी परिषद के 80 कार्यकर्ता ने भाग लिया।

कार्यकरणी गठन में विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री देवांश चन्देल उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा की कार्यकारिणी किसी भी संगठन का आधार होती है और यह ही संगठन की दिशा व दशा को तय करती है।

मोदी के तेवर देख सब हैरान, बाजारों की रौनक गुम

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर रोक लगने के फैसले से चारों तरफ अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई है। तात्कालिक तौर पर आम लोग इस फैसले से परेशान दिख रहे हैं। वहीं एक बड़ा तबका इससे खुश भी हैं और उनका

कहना है कि इससे काले धन पर रोक लग पाएगी। कांगड़ा जिले में भी मोदी के इस फैसले का काफी असर देखा गया। यहां के बाजारों में आज बहुत कम चहल-पहल देखी गई। वहीं कई दुकानदार पांच सौ और एक हजार के नोटों के लेनदेन में ना-नुकर करते दिखे।

प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसला का लोग समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन इससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को काफी नुकसान झलने पड़ा रहा है। सुनील वर्मा एक सुनार की दुकान चलाते है। उन्होंने कहा कि मोदी का फैसला बहुत अहम है। पर इसके चलते ग्राहक काफी ज्यादा परेशान है जिसकी वजह से उनके पास आज कोई ग्राहक नहीं आया। वर्मा ने कहा कि शादियों का सीजन होने के बावजूद उनकी दुकान पर गिने-चुने ग्राहक ही आ रहे हैं।

कपड़ों का व्यापार करने वाले अमित कपूर ने कहा की जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है उनकी दिक्कत हो सकती है जबकि ईमानदार लोगों को इस फैसले से जरा सा भी घबराने की जरूरत नही है। कपूर का भी मानना है कि इससे उनकी बिक्री पर खासा फर्क पड़ा है।

शाहपुर में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि शादी के सीजन के चलते उन्हें बहुत दिक्कते महसूस हो रही है। इस फैसले से राशन, कपड़ों और गहनों की खरीददारी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही लोगो को रोजमर्रा के सामान खरीदने में दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

यही नहीं हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बसों में सफर करते वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। न्यू मीडिया की छात्रा युक्ति डडवाल ने बताया कि बस परिचालक पांच सौ और एक हजार के नोटों को लेने से साफ इंकार कर रहे हैं।

सीयूएचपीके हिन्दी विभाग में कार्यरत प्राध्यापक चंद्रकांत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इससे काले धन, भ्रष्टाचार और हवाला के तहत चल रही अवैध गतिविधियों पर रोक लग पाएगी और देश की आर्थिक दशा सुधरेगी।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बैंकों और डाकघरों में 30 दिसंबर तक बदला जा सकेगा और इसके बाद पुराने नोट की कोई भी मूल्य नहीं बचेगा।

ABVP के रक्तदान कैंप के लिए अड़ंगा फिर भी हुआ 40 यूनिट खून एकत्रित

शिमला/शैल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर में आयोजित इस रक्तदान कैंप की खास बात ये रही कि इसमें छात्राओं की भागीदारी छात्रों से ज्यादा रही।

विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष साहिल परमार ने कहा इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक तथा मनुष्य की सहायता करना था।

एबीवीपी के छात्रों के माने तो पहले अस्पताल प्रशासन इस कैंप में आने के लिए तैयार नही था लेकिन जब परिषद के छात्रों ने धमकी दी कि वो प्रदर्शन करेंगे तो अस्पताल प्रशासन मान गया।

रक्तदान शिविर में 40 छात्र व छात्राओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में धर्मशाला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने शिरकत की।

एबीवीपी की ओर से आयोजित

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसम्बर से धर्मशाला में

शिमला/शैल।। यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में मुख्य मंत्री शिक्षक सम्मान योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों टीजीटी, पीजीटी मुख्य अध्यापकों, प्राधानाचार्य को विशेषकर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी इत्यादि विषयों में समग्र बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे अध्यापक जो शत-प्रतिशत परिणाम देगें उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार व वित्तीय लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 2016 के बजट भाषण में की थी, जिसमें कहा गया था कि जो अध्यापक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में निरन्तर शत-प्रतिशत परिणाम देंगे। उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा।

मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

बैठक में 19 से 23 दिसम्बर तक राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप /नवाचार परियोजना, नई औद्योगिक योजना को भी मंजूरी प्रदान की। जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार, रोजगार सृजन और उद्यमियों की कौशल का स्तरोन्नयन के अतिरिक्त हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना है, जिनमें व्यावसायिक मार्गदर्शन इत्यादि भी शामिल है। योजना का उद्देश्य उद्यमियों को निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संभावित क्षेत्रों में उपयुक्त परियोजनाएं चयनित करने में एद्यमियों को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त उनके उद्यमों का व्यावसायिक रूप प्रबन्धन करने में सहायता प्रदान करना है।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्र सरकार के मंत्रालय तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों, जिनमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, रेलवे और रक्षा मंत्रालय इत्यादि शामिल हैं, के लिए प्रदेश में विभिन्न भू अधिग्रहण प्रक्रिया की पहल पर हरियाणा, बिहार, असम इत्यादि राज्य की तर्ज पर 9 प्रतिशत की दर से राज्य प्रशासनिक तथा आकस्मिक शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने 4000 और उससे अधिक विद्यार्थियों की संख्या को राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 में यूजी स्तर पर 'शिक्षा' को नए विषय के रूप में आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए बेहतर नींव उपलब्ध होगी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016 के तहत भरने का निर्णय लिया, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती से इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में विभिन्न सुपर स्पेशियलिटि विभागों में प्रौफेसर, एसोसियेट प्रौफेसर और एसिस्टेंट प्रौफेसर के छह पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 100 पदों को करूणामूलक नियुक्ति से भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देकर चालक आपरेटरों के 83 पदों को ऐसे नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके पास वैध ड्राइविंग/आप्रेटर लाईसेंस है तथा जो पहले ही वाहन मशीनरी पर तैनात हैं, में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित बैकलॉग के तहत विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुबंध आधार पर निवार्चन कानूनगो के पांच पदों को भरने की स्वीकृति।

बैठक में उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रबन्धक डीआईसी राजपत्रित श्रेणी दो के तीन पदों को भरने की स्वीकृति।

बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक विभाग में ड्रग निरीक्षक के 22 पदों और सहायक ड्रग नियंत्रक के तीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान।

बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक रेंजिज के लिए स्टाफ अधिकारियों के तीन पदों के सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

हाल ही में 200 बिस्तरों वाले स्तरोन्नत नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए चिकित्सा अधीक्षक के एक पद को सृजित करने की मंजूरी।

बैठक में परिवहन विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के तीन पदों को भरने की स्वीकृति।

मंत्रिमण्डल ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप सहायक पर्यटक विकास अधिकारियों के हाल ही में सृजित दो पदों तथा निरीक्षक (होटल) के तीन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में चौकीदार के दो पदों को सृजित करने पर सहमति।

बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में एनआईईएलआईटी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर पद्धति विश्लेषक के एक पद को सृजित व भरने की मंजूरी।

बैठक में शिमला जिला के धामी के समीप 16 मील स्थित राजकीय महाविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा के सहायक प्राध्यापक के एक पद के सृजित करने की मंजूरी।

बैठक में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में ड्रामा निरीक्षक के एक पद तथा स्टेज मास्टर क्लास थ्री यगैर राजपत्रित के एक पद को अनुबंध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत फनोती में आवश्यक स्टाफ सहित स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने को दी स्वीकृति।ऊना जिला के बसाल में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वी ति।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के कोटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊना जिला के थानाकलां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांगड़ा जिला के मझीन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक स्टाफ सहित स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के श्वाद में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवश्यक स्टाफ सहित खोलने की मंजूरी की प्रदान।

मंत्रिमण्डल ने 31 मार्च 2016 को मनरेगा के अन्तर्गत 1004 तकनीकी सहायकों, जिन्होंने पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, को दिहाड़ीदार बनाने तथा मनरेगा के अन्तर्गत 26 सितंबर 2012 से कार्य कर रहे 663 तकनीकी सहायकों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रदेश के लोगों को राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रापण तथा वितरण प्रणाली के तहत ग्रुप। में काले चने प्राप्त करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने भरमौर के आईटीडीपी यात्री निवास को परिधि गृह में बदलने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिला के रियात खण्ड के अन्तर्गत गांव दराला तथा पत्तन,शाहपुर) में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के उपर तकारला गांव तथा नेहरी पंचायत के गांव खरोटा में प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लोक निर्माण विभाग सी अनुभाग को सृजित कर उपयुक्त स्टाफ मुहैया करने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजगढ़ पुलिस थाने के अन्तर्गत फटी पटेल के पझौता में पुलिस चौकी खोले को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के कन्दरौड़ी में आऊट पोस्ट राजकीय रेलवे पुलिस को दोबारा खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में लाहौल-स्पिति जिला के झालमा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय लिया गया। कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत धौगी के रूवाड़ गांव में पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने उप-तहसील देहा के घुंड तथा बगेन पटवार वृत्त को ठियोग तहसील में जोड़ने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य में पांच निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई तथा आठ निजी नर्सिंग संस्थानों में विभिन्न पाठयक्रम आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कांग्रेस का मौन प्रदर्शन,सिर पर सफेद टोपी-मुंह पर काली पटटी,पूर्व वामपंथी नेत्री के हाथ में कांग्रेसी झंडा

शिमला/शैल। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को मोदी सरकार की ओर से हिरासत में लेने व मीडिया पर हमला करने के विरोध में मुंह पर काली पट्टी बांध कर किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सफेद टोपी पहन कर इस प्रदर्शन में शामिल हुए तो पूर्व वामपंथी नेत्री मीरा कांग्रेस का झंडा उठाए रही। मीरा ने हाल ही में सभी को चौंकातें हुए वामपंथी संगठन सीपीएम को अलविदा कह कर कांग्रेस का दामन थामा था।

प्रदर्शन स्थल सीटीओ के समीप लाल बहादुर शास्त्री चौक पर कांग्रेस का जत्था 12 बजे तक भी नहीं पहुंचा था जबकि उन्हें साढ़े ग्यारह बजे पहुंचना था। वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जेनब चंदेल समेत कई नेता कांग्रेस के जत्थे के आने का इंतजार करते रहे।

सवा बारह बजे के करीब कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का काफिला लाल बहादुर शास्त्री चौक की ओर आया और यहां पर शास्त्री के प्रतिमा के नीचे मूक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की खास बात ये रही कि इसमें पहले के प्रदर्शनों के मुकाबले कांग्रेसियों की अच्छी तादाद रही। शायद मामला राहुल गांधी का था।प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के लाडले विक्रमादित्य सिंह ने भी शिरकत की।

इस मौके पर सुखविन्दर सिंह सुक्खु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यप्रणाली हमेशा से दमनकारी, तानाशाही व लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत रही है। उन्होंनें कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकतन्त्र की हत्या करने का ताजा उदाहरण हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने से रोकना व गिरफ्तार करना तथा लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के अधिकारों का हनन करते हुए एनडीटीवी के प्रसारण पर रोक लगाना है। उन्होंनें कहा कि मोदी सरकार लोकतन्त्र की धज्जियां उड़ाते हुए आम लोगो व मीडिया के अधिकारो का हनन कर रही है और संविधान मे मिले अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है जो कि देश के लिए बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है।

उन्होंनें कहा कि मोदी सरकार द्वारा वन रैंक-वन पैंशन पर भूपपूर्व सैनिकों को गुमराह किया गया। पूर्व सैनिक के आत्महत्या करने पर उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के बजाय पूर्व सैनिक के परिवार को गिरफ्तार कर दिया। इससे दिल्ली पुलिस की गुण्डागर्दी वाली कार्यप्रणाली सबके सामने उजागर हुई है।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयन्ती पर दी बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरूजी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शाति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होने कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्वबन्धुत्व पर बल दिया तथा उनकी शिक्षाएं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में और भी प्रासंगिक हो जाती हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

स्कैंडल की गप–शप

यह कैसी सर्वश्रेष्ठता

हिमाचल सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इण्डिया टुडे ने सर्वश्रेष्ठता का ईनाम दिया है। **शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य में क्या काम हुआ है? वहां शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। साक्षरता की दर क्या है। ड्रॉपआऊट की स्थिति क्या है? भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों की स्थिति क्या** है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बड़े स्कूलों में बी पी एल के कितने बच्चों को दाखिला मिला है। ऐसे कई मानदण्ड है जिनका व्यवहारिक आकलन किये बिना प्रदेश की शिक्षा स्थिति का सही मूल्यांकन नही किया जा सकता है। इस पत्रिका को इन मानदण्डों पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का आकलन करके क्या अध्ययन रहा है इसकी कोई औपचारिक सूचना प्रदेश सरकार के पास नही मिल पायी है।

वैसे जिस दौरान यह आवार्ड दिया जा रहा था उसी दौरान प्रदेश के कई भागों से यह समाचार आ रहे थे कि लोगों ने स्कूल में पर्याप्त अध्यापक न होने के कारण सामूहिक रूप से बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है। पिछे जब कई स्कूलों के परीक्षा परिणाम शून्य रहने पर ऐसे अध्यापकों के खिलाफ कारवाई करने की कवायद की जाने लगी थी तो उसे अन्तिम क्षणों में रोक दिया गया था क्योंकि इसका कारण अध्यापकों की कमी मिला था। अब सरकार ने शत–प्रतिशत परिणाम देने वाले अध्यापकों को ईनाम के रूप सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है। वैसे इस शिक्षक सम्मान योजना की घोषणा मुख्यमन्त्री ने अपने बजट भाषण में की थी जिस पर अब अमल करने की बात आ रही है।

इस समय प्रदेश में स्कूलों की संख्या हजारों में है जहां तय मानदण्डो से बच्चों और अध्यापकों दोनों की संख्या कम है। ऐसे भी स्कूल है जहां एक ही छात्र है और एक ही अध्यापक है। मुख्यमन्त्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जहां एक भी बच्चा पढने वाला होगा वह वहां स्कूल खोलेंगे। लेकिन अब व्यवहारिकत्ता का ज्ञान होने के बाद हजारो स्कूलों को बन्द करने का फैंसला लिये जाने की स्थिति आ गयी है। अभी सौ स्कूलों को बन्द करने का फैसला लिये जाने की स्थिति आ चुका है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है इसलिये बतौर मुख्यमन्त्री उनकी घोषणाएं अलग अर्थ रखती है। लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री वह इन घोषणाओं पर अमल करने की स्थिति में नही है। ऐसे में चर्चा यह चल पड़ी है कि सर्वश्रेष्ठता का मानदण्ड घोषणाएं है या उन पर अमल न हो पाना है।

वित्तिय संकट के कगार पर पहुंची प्रदेश सरकार केन्द्र के पत्र से उभरे संकेत

शिमला/शैल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने मण्डी रैली में प्रदेश की जनता के सामने यह खुलासा रखा था कि केन्द्र सरकार ने 14वें वित्तायोग के तहत हिमाचल प्रदेश को 72 हजार करोड़ रूपया दिया है। मोदी ने जनता से यह भी आवाहन किया था कि वह सरकार से इस पैसे का हिसाब भी मांगे। उन्होने यह भी कहा था कि केन्द्र सरकार भी इसका हिसाब मांगेगी। मोदी के इस खुलासे पर सरकार में गंभीर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। मोदी ने इस खुलासे के बाद मुख्यमन्त्री द्वारा अपनी जनसभाओं में की जा रही घोषणाओं में भी एक बदलाव देखने को मिला था। अब मुख्यमन्त्री जनता को कुछ भी देते हुये ये भी कह रहे हैं कि जो वो दे रहे हैं उसका सही पता तभी चलेगा जब वह बतौर वित्तमन्त्री इस घोषणा से जुड़ी फाईल को देखेंगे। वित्त विभाग ने भी अब घोषणाओं का औचित्य आंकलन करते हुये बहुत सारी घोषणाओं पर यह लिखना शुरू कर दिया है कि इसमें मुख्यमन्त्री की घोषणा के अतिरिक्त और कोई आधार नही बनता। बहुत सारी घोषणाओं पर अब अन्तिम अधिसूचनाएं रोक दी गयी हैं। बल्कि वित्तिय कठिनाईओं को देखते हुए कई संस्थानो को बन्द करने का फैंसला लिया जा रहा है इस संद्धर्भ में पहली कड़ी में 75 से 100 स्कूल बन्द किये जाने का फैंसला कभी भी बाहर आ सकता है।

इस समय सरकार की वित्तिय स्थिति के मुताबिक वर्ष 2002-2003 में जो कुल ऋण दायित्व 13209.47 करोड़ था वह 2014-15 में 35151.60 करोड़ हो गया तथा 2015-16 में 39939 हो गया है। वर्ष 2016-17 के बजट प्रस्तावों के मुताबिक इस वर्ष में 6102.38 करोड़ ऋण लेने का प्रावधान रखा गया है। इन आंकड़ो के मुताबिक इस वर्ष मे 31 मार्च 2017 को कुल कर्ज 46041 करोड़ हो जायेगा। दूसरी ओर केन्द्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रदेश सरकार को 29 मार्च 2016 को भेजे गये पत्र के मुताबिक राज्य सरकार अपने जीडीपी का कुल 3% ऋण ले सकती है। इस पत्र के मुताबिक वर्ष 2016-17 के लिए ऋण की तय सीमा 3540 करोड़ है। लेकिन सरकार ने बजट प्रस्तावों में ही 6102 करोड़ ऋण के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा तय ऋण की सीमा 3540 करोड़ और 6102 करोड़ में दिन रात का अन्तर है। सूत्रों के मुताबिक वित्त सचिव ने मुख्यमन्त्री को इस स्थिति से अवगत करवा दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वित्त विभाग में और वित्तिय दवाब का प्रबन्धन नही कर पायेगा। क्योंकि सरकार के इस कार्यकाल में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सरकार को कोई बड़ा निवेश नही मिल पाया जिससे की जीडीपी में बढ़ौत्तरी हो पाती।

दूसरी ओर अभी सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिये समान वेतन का फैंसला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि गैर रैगुलर कर्मचारियों को रैगुलर कर्मचारियों के बराबर ही वेतन देना होगा। पिछले काफी अरसे से सरकार सारी नयी नियुक्तियां कांट्रैक्ट के आधार पर ही करती आ रही है चाहे ऐसे कर्मचारियों का चयन प्रदेश लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से हुआ हो। वर्तमान नीति के अनुसार पांच साल का सेवा काल पूरा करने पर ही कांट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इस फैसले के तहत हर कर्मचारी को नियुक्ति के पहले दिन से ही रैगुलर के बराबर वेतन देना होगा। रैगुलर और कांट्रैक्ट कर्मचारी के बीच इस समय दस से पन्द्रह हजार वेतन का अन्तर है। सरकार में ऐसे कर्मचारियों की संख्या पचास हजार से अधिक है। इन कर्मचारियों को यदि नियमित के बराबर वेतन न मिला तो यह लोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऊपर से आगे विधान सभा चुनाव आने हैं और सरकार इन चुनावों को सामने रखकर मन्त्री मण्डल की हर बैठक में नये पद भरने और सृजित करने के फैंसले लेती जा रही है। चुनावों को लेकर की जा रही सारी घोषणाओं पर अमल करने के लिये वांच्छित वित्तिय संसाधन जुटाने का तरीका ऋण लेने के अतिरिक्त और कोई नही बचता है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा तय ऋण सीमा के भीतर रहकर सारे फैसलों पर अमल कर पाना संभव कैसे हो सकेगा। इस सवाल को लेकर वित्त विभाग और मुख्य सचिव क्या रास्ता निकालते है इस पर सबकी निगाहें लगी है।

यह है भारत सरकार का पत्र

No. 40(6) PF-I/2009 Vol.-II
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(Plan Finance-I Division)

North Block, New Delhi, the 29th March, 2016.

To

The Principal Secretary (Finance),
Government of Himachal Pradesh,
Finance Department,
Shimla- 160017
Fax: 0177-2621859/2624520/2621586

Subject: Annual Borrowing Ceiling for the financial year 2016-17.

Sir,

The net borrowing ceiling for the financial year 2016-17 for your State has been calculated as Rs. 3,540 crore considering base Fiscal Deficit target of 3% as recommended by Fourteenth Finance Commission (FFC).

2. The State may please ensure adherence with this ceiling while assessing resources for its Annual Plan for 2016-17, and also ensure that the State's incremental borrowings remain within this ceiling during 2016-17. The ceiling covers all sources of borrowings, including Open Market Borrowings, Negotiated Loans from financial institutions, National Small Saving Fund loans, Central Government loans including EAPs, other liabilities arising out of public account transfers under small savings, Provident funds, Reserve Funds, Deposits, etc., as reflected in statement 6 of the State's Finance Accounts. Further, in case the outstanding balances in Cash Credit Limits (CCL) Accounts for Food procurement operations, if any, by the State at the end of the financial year exceeds the opening balances at the beginning of the year, the net increase shall be considered against the borrowing space of the State for the year 2016-17. However, the additional borrowing limits proposed under UDAY to take over DISCOMs liabilities by participating States would be beyond the limits prescribed by the FFC and not to be counted against the Fiscal deficit limits of respective States as per decision taken.

3. It is requested that the details of liabilities arising out of all source of borrowings as indicated in para 2 above and repayments thereof during 2014-15(Actuals), 2015-16 (Actuals) and 2016-17 (Estimated) may be shared in the enclosed format latest by 14th April 2016 to update our records for 2014-15 & 2015-16 and to arrive at tentative allocation of borrowing space available to the States during 2016-17.

4. The GSDP estimate arrived at for the year 2016-17 in accordance with FFC recommendations duly adjusted for GDP growth adopted in Union Budget 2016-17 is Rs. 1,17,989 Crore. Please note that this GSDP estimate shall be used for evaluation of fiscal parameters for 2016-17.

6. Since the primary responsibility of remaining within the overall debt/GSDP norms recommended by FFC and the borrowing ceiling shall remain with the State, it is advisable to continually track the liabilities so that the State does not inadvertently breach its net annual borrowing ceiling. State may also calibrate its borrowings with expenditure requirements and approach the market after assessment of its treasury holdings.

Yours faithfully

(Manmohan Sachdeva)
Director
Tel: 23095691

क्या नेता घोषित किये बिना

...............पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा भी वीरभद्र के प्रति गंभीरता से आक्रामक नही हो पा रहे हैं। अब जब से नड्डा नेतृत्व की चर्चा में चल रही है तब से धूमल खेमा भी इस दिशा में खामोश हो गया है फिर अनुराग स्वयं ही बीसीसीआई में इतना उलझ गये हैं कि प्रदेश के लिये वह ज्यादा समय ही नही निकाल पा रहें हैं। धूमल को लेकर पार्टी के ही एक वर्ग ने उन्हें निकट भविष्य में राज्यपाल बनाये जाने की चर्चा फैला दी है। सूत्रों के मुताबिक जब पिछले दिनों एक दलित नेता को राज्यपाल बनाया गया था तब उन्हे बधाई देने पहुंचे एक ग्रुप में हिमाचल के भी एक-दो लोग थे। इन लोगों ने बधाई देने के उस मौके पर धूमल को राज्यपाल बनाने की गुहार लगा दी। यह लोग हरियाणा के खट्टर की तर्ज पर स्वयं को प्रदेश का अगला नेता मानने लग पड़े हैं। इन लोगों को कभी धूमल ने ही राजनीति में स्थापित होने का अवसर दिया था। आज यह ही धूमल को राज्यपाल बनाने का ताना बुनने में लग गये हैं। इन लोगों का तर्क है कि जब हरियाणा में खट्टर हो सकते हैं तो फिर हिमाचल में भी खट्टर जैसा ही कोई क्यों नही हो सकता। लेकिन हरियाणा और हिमाचल में एक मुल अन्तर है कि हरियाणा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। जबकि हिमाचल में चार बार सरकार बन चुकी है। भले ही शान्ता कुमार दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाये हों परन्तु धूमल ने दोनों बार सफलता पूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि उन्हें दोनो बार अपनों के भी विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा है।

आज भाजपा केन्द्र में सरकार होने और प्रदेश में वीरभद्र के मुख्यमन्त्री होते हुए भी लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर कब्जा करके थोड़ा प्लस में है। लेकिन यदि चुनावों से पहले किसी को नेता घोषित न किया गया तो स्थिति बहुत सुखद नही रहेगी। क्योंकि आज प्रदेश में भाजपा का मुकाबला वीरभद्र से होने जा रहा है और कांग्रेस ने अगला चुनाव उन्ही के नेतृत्व में लड़ने की अभी से घोषणा कर रखी है। भाजपा जिस गंभीरता से अगले चुनावों के लिये रणनीति बनाने में लगी हुई है उसमें नेतृत्व के प्रश्न पर उसकी अस्पष्टता उसके सारे प्रयासों पर भारी पड़ सकती है। इस समय नेतृत्व के लिये शान्ता-धूमल के अतिरिक्त नड्डा का नाम भी प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। इनके अतिरिक्त पूर्व अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज और जय राम ठाकुर का नाम भी कुछ हल्कों में चर्चा में है। भाजपा की कोर कमेटी की कसौली में हुई बैठक में भी नेतृत्व का प्रश्न गौण रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभितशाह 11 दिसम्बर को हिमाचल आ रहे हैं उस समय नेतृत्व के प्रश्न पर फैसला हो पाता है या नही यह तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि घोषित नेतृत्व के बिना कार्यकर्ताओं को पूरी आक्रामकता में बनाये रखना आसान नहीं होगा।